(ख) क्या राज्य की कुछ अन्य योजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ग) ऐसे बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें इस योजनाओं के अधीन रोजगार मिलेगा और इन्हें कितने दिनों के लिए मिलेगा;

(घ) कुल बेरोजगारों की तुलना में उपरोक्त (ग) के बेरोजगारों की संख्या का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए अन्य कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):** पूजारी) : (क) 1 अप्रैल, 1989 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है । इसलिए चालू वित्तीय वर्ष से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों के आवंटन को समाप्त कर दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 25618.79 लाख रुपए के संसाधन (राज्य अंश सहित) आवंटित किए गए हैं ।

(ख) जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश की गई कोई योजना/परियोजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत योजनाओं/निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को है ।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार का हिसाब श्रम दिवसों के रूप में लगाया जाना है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित संसाधनों से 1118.72 लाख श्रम दिवसों का रोजगार सृजित होने की सम्भावना है इससे प्रति व्यक्ति 100 दिनों की दर से लगभग 11.18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ।

(घ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार पाने वालों का प्रतिशत लगभग 35 प्रतिशत होगा ।

(ङ) जवाहर रोजगार योजना के अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु योजना ऐसे अन्य प्रमुख कार्यक्रम हैं जो बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

**मध्य प्रदेश में तांबे के कारखाने की स्थापना**

2309. **श्री अजीत जोगी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलंजखण्ड खानों से तांबा अयस्क निकाल कर उससे तांबा बनाने के लिये राजस्थान के खेतड़ी कारखाने में भेजा जाता है;

(ख) क्या सरकार राज्य के पिछड़े हुए आदिवासी जिलों के औद्योगीकरण के हित में मध्य प्रदेश में ही तांबे के कारखानों की स्थापना करने का विचार करेगी; और

(ग) क्या ऐसा करना आर्थिक व तकनीकी कारणों से भी लाभप्रद न होगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):** (क) मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट स्थित मलंजखण्ड ताम्र परियोजना के केवल तांबा सान्द्रों का उत्पादन होता है । खेतड़ी कापर कम्पलेक्स, राजस्थान में उपलब्ध अतिरिक्त प्रद्रावण क्षमता का उपयोग मलंजखण्ड ताम्र

परियोजना से तांबा सान्द्रों से तांबा धातु की निकासी, खेतड़ी कापर कम्पलेक्स भेजकर की जाती है ।

(ख) तांबा धातु के उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश में यूनिट लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**मध्य प्रदेश के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था**

2310. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां पर शुद्ध और स्वास्थ्यकर पीने के पानी की सुविधा अभी तक भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;

(ख) ऐसे गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है;

(ग) शेष प्रत्येक गांव में कब तक पीने के पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करने की संभावना है; और

(घ) देश में मध्य प्रदेश जैसे ऐसे कितने राज्य हैं जहां कोई गांवों में अभी भी पीने के पानी की सुविधा का अभाव है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) 1 जुलाई, 1989 को मध्य प्रदेश में 351 "जल स्रोत रहित समस्याग्रस्त गांव" थे, जिन्हें अभी स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी हैं ।

(ख) 1989-90 के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 31.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 25.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । राज्य सरकार को इन "जल स्रोत रहित समस्याग्रस्त गांवों" तथा आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के आवंटन की पूरी राशि रिलीज कर दी गई है ।

(ग) इन सभी गांवों को 31 मार्च, 1990 तक स्वच्छ पेयजल सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी ।

(घ) देश में मध्य प्रदेश जैसे 20 अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं, जहां ऐसे कई जल स्रोत रहित समस्याग्रस्त गांव हैं जहां अभी भी पेयजल की सुविधा का अभाव है ।

**मध्य प्रदेश में बाढ़ और सूखे से हुई हानि**

2311. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में औसतन प्रत्येक वर्ष कितनी कृषि योग्य भूमि बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित होती ;

(ख) इससे प्रतिवर्ष औसतन कितनी हानि होती है ; और

(ग) इस प्रकार की हानि से बचने के लिए सरकार ने क्या पहल की है और इस प्रयोजन के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

**कृषि मंत्री (श्री भजन लाल)** : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सूखे से